मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमान (MMRCA) संबंधी भारत का समझौता:
मूल औचित्य में ही घाल-मेल, महँगा जोखिम ?
India's MMRCA Deal: Muddled Rationale, Costly Adventure?

विपिन नारंग
Vipin Narang
10.26.09

यद्यपि 2008 का भारत-अमरीकी परमाणु सौदा बहुत ही बड़ा राजनैतिक नाटक माना जाता है लेकिन 126 मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) की $10 बिलियन डॉलर की भारत की प्रस्तावित खरीद का भारत के रणनीतिक संबंधों पर जो प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है, वह उससे कहीं ज़्यादा होगा. खास तौर पर यह प्रभाव उस हालत में और भी गहरा हो जाएगा यदि अमरीकी प्लेटफॉर्म के लॉकहीड के एफ़-16 ई/एफ़ या बोइंग के एफ़/ए-18 ई /एफ़ का चयन विजेता बोली के रूप में कर लिया जाता है.वास्तव में उड़ने के लिए तैयार होने की अवस्था में होने पर भी पहले अठारह विमान कम से कम 2014-15 से पहले तो भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल नहीं हो पाएँगे और शेष 108 विमान,जिन्हें भारत में ही असेम्बल किया जाना है, कम से कम 2022 से पहले ऑपरेट नहीं हो पाएँगे. इससे अस्थायी समाधान के रूप में प्रस्तावित चौथी पीढ़ी के युद्धक विमानों के समझौते के कारण सामरिक उपयोगिता से होनेवाला रणनीतिक प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और जब तक इनकी तैनाती होगी, ये पुराने भी पड़ जाएँगे. इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भारतीय वायुसेना की अन्य भारी जरूरतों की तुलना में यह समझौता सचमुच किसी काम का है भी या नहीं.

भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने चौथी पीढ़ी के 126 मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के प्रस्ताव का अनुरोध आखिर क्यों किया? भारतीय वायुसेना के पास इस समय तीस–बत्तीस युद्धक विमान स्क्वैड्रन ऑपरेशन में हैं. 39.5 स्क्वैड्रन के वैधानिक स्तर से यह संख्या बहुत कम है और जब अगले दशक में मिग-21 के लगभग सत्ताइस से उनतीस स्क्वैड्रन पुराने पड़ जाएँगे और इस कारण उनकी भरपाई के बिना ही ऑपरेशन से हटा लिए जाएँगे तो यह संख्या तब और भी कम होकर सत्ताइस – अट्ठाइस तक रह जाएगी. युद्धक विमानों की घटती संख्या के कारण भारतीय वायुसेना तैनाती के स्वरूप को बनाए नहीं रख सकती और आत्मरक्षा के लिए आवश्यक ऑपरेशनल तैयारी भी नहीं रख सकती. पाकिस्तान की तुलना में खास तौर पर तब जब वह आगामी वर्षों में एफ़-16 के ऑर्डर की डिलीवरी ले लेगा, भारतीय वायुसेना की स्थिति बेहतर नहीं रह पाएगी. यही कारण है कि भारतीय वायुसेना और

रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं में इनकी घटती संख्या के आसन्न खतरे को भाँपकर कई साल पहले ही पुराने युद्धक विमानों को बदलने के लिए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे.

एक विकल्प तो यह था कि हल्के युद्धक विमान मिग-21 स्क्वैड्रन के स्थान पर उसी तरह के अधिक क्षमता वाले मिग-29, फ्रेंच मिराज जैसे आधुनिक विमान ले लिए जाएँ. स्वदेश में ही विकसित तेजस जैसे हल्के युद्धक विमानों के कारण, जो कमोबेश आधुनिक मिग-21 की श्रेणी और क्षमता के ही हैं, मिग-21 स्क्वैड्रन के स्थान पर विदेशी विमान जुटाने की ज़रूरत कम पड़ गई. तेजस में इंजन की समस्या के कारण अगस्त 2009 में आकर अधिक क्षमता वाले इंजनों की खोज नए सिरे से शुरू कर दी गई; इसलिए भारतीय वायुसेना ने अगले कई वर्षों तक अपने ही पहले ऑपरेशनल तेजस विमान की डिलीवरी लेना टाल दिया है. इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2002 से ही मध्यम-से-भारी प्लेटफ़ॉर्म वाले रूसी इंटरसेप्टर, बमवर्षक और जमीनी हमला करने में अत्यंत सक्षम और परिवर्तनशील 4.5 पीढ़ी के सु-30 एमकेआई को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था और देशी तौर पर हिंदुस्तान ऐरोनॉनिक्स (HAL) ने इसे उत्तरोत्तर असेम्बल करना शुरू कर दिया था. 2015 तक भारतीय वायुसेना में कुल मिलाकर ऐसे 280 सु-30 एमकेआई शामिल किए जा चुके होंगे. तेजस और सु-30 एमकेआई दोनों मिलकर ही अगले दशक के मध्य में 2022 तक पूरी आक्रामक क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली परिसंपत्तियों की भरपाई कर देंगे.

दूसरा विकल्प यह था कि समस्त प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से बदल डाला जाए और नेटवर्क केंद्रिक परिवेश में ऑपरेट करने में सक्षम पाँचवीं पीढ़ी के अमरीकी एफ़-22 या एफ़-35 या रूसी सुखोई पीएके-एफ़ए जैसे युद्धक विमान प्राप्त कर लिए जाएँ. भारत और रूस सैद्धांतिक रूप में इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सुखोई पीएके-एफ़ए को संयुक्त रूप में विकसित किया जाए. यह मोटे तौर पर मध्यम दूरी तक मार करने वाले विमान की भार-श्रेणी में ही होगा हाल ही में सेवानिवृत्त एयर चीफ़ मार्शल फ़ाली मेजर ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि 2020 के आसपास पाँचवीं पीढ़ी के युद्धक विमान ऑपरेशनल हो जाएँगे. यद्यपि 2015 तक भारतीय वायुसेना की लक्ष्यवेधित मारक क्षमता अपेक्षित स्तर से नीचे ही होगी,किंतु तेजस और सु-30 एमकेआई तथा वास्तविक अर्थों में पाँचवीं पीढ़ी के सुखोई पीएके-एफ़ए विमान के पूरे बेड़े के वायुसेना में शामिल होने के साथ ही तैनाती और प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. इस प्रकार भारतीय वायुसेना हल्के और मध्यम-से-भारी बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों के मिले-जुले बेड़ों के साथ लक्ष्य को सही तौर पर बेधने और मिशन कामयाब करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगी.

ऐसी स्थिति में मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) का भारतीय वायुसेना में क्या स्थान होगा ? इसकी आरंभिक परिकल्पना सन् 2001 में मिग-21 के बेड़े के

स्थानापन्न के रूप में अंतरिम समाधान के तौर पर कहीं अधिक सक्षम 4.5 पीढ़ी के 126 युद्धक विमानों के सैट के साथ की गई थी. मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमान (MMRCA) छह श्रेणियों में सिंगल और दो-इंजन वाले विमानों के साथ मिले-जुले रूप में थे. इन्हें मोटे तौर पर मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है: एफ़-16 ई/ एफ़ (एफ़-35 के मोटे भावी विकल्प के साथ), एफ़/ए-18 ई / एफ़, दसॉल्ट रेफ़ेल, यूरोफ़ाइटर टायफ़ून, साब ग्रिफ़ेन एनजी और रूस का मिग-35. इन छह विमानों का इस समय भारतीय वायु सेना में कई प्रकार की मुठभेड़ों के परिवेश में बेंगलोर, जैसलमेर और लेह में परीक्षण चल रहा है. भारतीय वायु सेना द्वारा ये परीक्षण हथियारों के मूल्यांकन के लिए कम से कम अगले साल तक भारत में और अन्य देशों में जारी रहेंगे.

जैसे ही भारतीय वायु सेना अपनी सिफ़ारिश रक्षा मंत्रालय को भेज देगी, भारत की नौकरशाही ठेका देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी. जेन्स डिफ़ेन्स वीकली के राहुल बेदी के अनुसार यह प्रक्रिया 2012-14 तक चलती रहेगी और अंतिम निर्णय लेने का मानदंड कतई स्पष्ट नहीं है. पहले अठारह विमान ठेके के तीन वर्षों के बाद उड़ने की अवस्था में तैयारशुदा मिलेंगे और प्राप्ति की प्रक्रिया में अगर थोड़ा भी विलंब हुआ तो मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के प्लेटफ़ॉर्मों की पहली डिलीवरी अगले दशक के उत्तरार्ध में ही मिल पाएगी. शेष 108 विमानों के स्वदेश में ही निर्माण की प्रक्रिया भी समयसाध्य है और चुने हुए प्लेटफ़ॉर्म के अनुरूप उनके निर्माण की अवधि भी अलग-अलग ही होगी. कुछ मामलों में यह अवधि 15 वर्ष भी हो सकती है. मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के अधिकांश विमान भारतीय वायु सेना में शामिल होने से पहले इस काम में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 15 साल तो लग ही जाएँगे.

यह विस्तृत समयमान मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के समझौते के मुख्य औचित्य को ही कम कर देता है. तेजस और सु-30 एमकेआई पहले अठारह मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) की डिलीवरी से काफ़ी पहले ही ऑपरेशनल हो जाएँगे और पाँचवीं पीढ़ी के सुखोई पीएके-एफ़ए युद्धक विमान लगभग ठीक उसी समय डिलीवर होंगे जब स्वदेश में ही मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमान (MMRCA) बनने लगेंगे. $10 बिलियन डॉलर के मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के कॉम्प्लिमेंट का समय वही हो सकता है जो भारतीय वायु सेना में इनके शुमार होने का समय होगा और इसके तीन दशक के समय चक्र का अंत भी तभी होगा. निश्चय ही सु-30 एमकेआई के विस्तृत ऑर्डर में मोटे तौर पर उसी प्रकार की क्षमताएँ होंगी. यद्यपि इसमें

“सक्रिय इलैक्ट्रॉनिक रूप में स्कैन्ड ऐरे” (AESA) रडार की कमी है, लेकिन इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है.

इस मत के आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) का यह समझौता कुछ हद तक भारी सु-30 एमकेआई और तेजस के टेक ऑफ़ के वेट्स के बीच भारत को आवश्यक क्षमता प्रदान करते हुए अपना “ऑपरेशनल एनवलप” विस्तृत करने का अवसर प्रदान करता है. यथास्थिति बनाए रखने की शक्ति के लिए स्वाभाविक रूप में सवाल उठता है कि भारतीय वायुसेना का विस्तार वस्तुतः और कहाँ होना है. ऐसे कौन-से वे विशिष्ट मिशन और भूमिकाएँ हैं जिनमें अंतराल रह जाएगा? मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के लिए किसी स्पष्ट भूमिका का अंतराल दिखाई नहीं पड़ता, जिसे भारतीय वायुसेना के वर्तमान युद्धक विमान और तेजस एवं सु-30 एमकेआई मिलकर भर न सकते हों. प्रस्तावित युद्धक विमान पाँचवीं पीढ़ी के हैं और पूरी तरह से वास्तविक क्षेत्रीय और आकस्मिक हमलों से निपटने में उनकी क्षमता की भी पर्याप्त जाँच की जा चुकी है. ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना की कुछ और क्षमताएँ हैं, जिन्हें बढ़ाने के लिए निवेश किया जा सकता है और जिनसे और भी अधिक सामरिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं. बड़ी टिकट की मदें गौरवमयी और सेक्सी ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना को लाभ तभी होगा जब उनकी क्षमताएँ निर्धारित भूमिकाओं के लिए चिह्नित हों. खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में संयुक्त रूप से सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए करीब से जमीनी सपोर्ट देने वाले विमान (जैसे, ए-10 थंडरबोल्ट्स) परिवहन, बहुत ऊँचे शिखरों पर हमला करने में सक्षम हैलिकोप्टर हों और आकस्मिक हमलों का मुकाबला करने के लिए निगरानी रखने या मुठभेड़ करने वाले ड्रोन क्षमतायुक्त विमान हों.

रणनीतिक रूप में मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमान (MMRCA) संबंधी समझौता भारत को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिससे वह संयुक्त राज्य अमरीका के साथ ऐसा रिश्ता कायम कर सकता है जिससे कि अधुनातन हथियारों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके. हाल ही में भारत ने अमरीका से पी-8 टोह लेने वाले समुद्री विमान और सी-130 परिवहन विमान प्राप्त किए हैं. इससे मुख्य लाइन के प्लेटफ़ॉर्म के लिए भारत की रूस पर निर्भरता भी कम हो जाएगी. हाल ही में गोश्कोव की देरी और फुटकर पुर्जों की लगातार कमी के कारण भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को काफ़ी निराशा हुई थी. अमरीका के अग्रणी युद्धक विमान के चयन से भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में एक ऐसे जलक्षेत्रीय आंदोलन की शुरूआत होगी जो अपने आप में रूसी प्लेटफ़ॉर्म से अलग हटने संबंधी नीतिगत परिवर्तन का पहला महत्वपूर्ण संकेत होगा और अमरीका के साथ भारत के गहन व्यावसायिक और सैनिक संबंधों में खास तौर

पर फुटकर पुर्जों, हथियारों, ऑपरेशनल प्रशिक्षण और समन्वित क्लाएँट-साइड संबंधों में और मजबूती लाएगा.

यद्यपि इस समय भारतीय वायुसेना छब्बीस अलग-अलग तरह के विमान-प्लेटफ़ॉर्मों को सपोर्ट करती है, फिर भी इस परिवर्तन के कारण भारत अपने परंपरागत आपूर्तिकर्ताओं रूस और फ्रांस से दूर होता जाएगा, इसलिए उसे भारतीय वायुसेना के लिए अलग से उत्पादन, रखरखाव, हथियार जुटाने और प्रशिक्षण की गंभीर व्यवस्था करनी होगी. यह ठीक है कि मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के समझौते में स्वदेश में 50 प्रतिशत के निर्माण की वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन कठोर लाइसेन्सिंग और निगरानी की व्यवस्था के कारण अमरीका कुछेक संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी स्तर पर निर्माण के लिए भारत को अनुमति देने से इंकार भी कर सकता है. यद्यपि व्यापक रणनीतिक संबंध निश्चय ही दोनों देशों के हित में हैं, लेकिन मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के समझौते को रामबाण के रूप में अंतिम नहीं मान लिया जाना चाहिए. खास तौर पर कुछ और भी वाणिज्यिक क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को सरलता और गहनता से ऑपरेशनल किया जा सकता है. यदि भारत का मुख्य उद्देश्य अमरीका के साथ गहन स्तर पर हथियारों के संबंध बनाना है तो ज़्यादा उचित तो यही होगा कि वह मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के बजाय पाँचवीं पीढ़ी के अमरीकी विमान प्राप्त करने का प्रयास करे.

मध्यम दूरी के बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) के समझौते का स्वरूप कुछ ऐसा है कि यह ऐसे गंभीर सवाल उठाने के लिए विवश कर रहा हैः क्या थोड़ा सा अंतराल भरने के लिए, जिसे सु-30 एमकेआई से अच्छी तरह भरा जा सकता है और अंततः लगभग उसी समय पाँचवीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के ऑन लाइन आने के बाद तो वे वैसे ही पिछड़ जाएँगे , $10 बिलियन डॉलर का खर्च करने का कोई औचित्य है? टायफ़ून और ग्रिफेन खरीदना भारत के लिए कोई अर्थ नहीं रखता. नया प्लेटफ़ॉर्म होने के कारण भारतीय वायुसेना में उन्हें शामिल करना काफ़ी महँगा साबित हो सकता है और इससे स्पष्ट रूप में कोई अतिरिक्त रणनीतिक या सामरिक लाभ भी नहीं मिलेगा. मिग-35 और रैफ़ेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करना अधिक आसान होगा,लेकिन इससे कोई खास लाभ नहीं होगा. एफ़-16 और एफ़-18 की खरीद से महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इन्हें ऑपरेशनल करने में काफ़ी खर्चा होगा. यदि इसका मुख्य उद्देश्य अमरीका के साथ गहरे स्तर पर रणनीतिक संबंध बनाना और रूस से दूरी बनाना है तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ किफ़ायती उपाय भी किए जा सकते हैं. रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना दोनों को ही स्पष्ट शब्दों में बताना होगा कि मध्यम दूरी के

बहुभूमिका वाले युद्धक विमानों (MMRCA) की प्राप्ति से क्या लाभ होगा और इस बात का गंभीरता से आकलन करना होगा कि अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को छोड़कर इस पर इतनी वित्तीय और संगठनात्मक लागत लगाना कितना औचित्यपूर्ण होगा. बाहर से देखने पर तो लगता है कि इसका औचित्य सिद्ध करना आसान नहीं होगा.

विपिन नारंग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शासन विभाग में पीएच डी के प्रत्याशी हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले से संबंधित बेलफ़ेर केंद्र में अनुसंधान फ़ैलो हैं. 2010 के पतझड़ सत्र में वे एम आई टी में राजनैतिक विज्ञान के सहायक प्रोफ़ेसर हो जाएँगे.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा),रेल मंत्रालय, भारत सरकार

<malhotravk@gmail.com>